प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट अपील संख्या 309 / 2021

अमित कुमार जयसवाल पिता गोपाल प्रसाद जयसवाल उम्र लगभग 41 वर्ष पर्यवेक्षक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर, निवासी सरंक्षक– बिजयकांत जयसवाल, रघुबीर एन्क्लेव, फ्लैट नंबर 101, वेयरहाउस रोड,तहसील एवं जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

----अपीलकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी न्यायाधिकरण द्वारा अध्यक्ष, पुराना बस स्टैंड, बिलासपुर छत्तीसगढ़
2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेहरू चौक, तहसील एवं जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़.
3. पंजीयक सहकारी समिति, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, पी.ओ./पी.एस. नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

रिट अपील संख्या 438/2022

• अंशुमान पांडे पुत्र श्री संतोष कुमार पांडे आयु लगभग 37 वर्ष निवासी सतबहनिया मंदिर के पास, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

---- अपीलकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रमुख सचिव सहकारी संस्थाएं, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी न्यायाधिकरण द्वारा अध्यक्ष, पुराने बस स्टैंड के पास, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
3. रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन , नया भवन, पी.ओ./पी.एस. नया रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेहरू चौक, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

---- उत्तरवादी

(वाद शीर्षक सूचना प्रणाली से लिया गया है।)

रिट अपील 309/2021 में अपीलकर्ता के लिए	: श्री दिलीप कुमार स्वाई, अधिवक्ता
रिट अपील 438/2022 में अपीलकर्ता के लिए	: श्री अमन सक्सेना, अधिवक्ता
रिट अपील संख्या 309/21 में उत्तरवादी 1 से 3 और रिट अपील संख्या 438/2022 में उत्तरवादी 1 से 3 के लिए	: श्री आर. प्रधान, अतिरिक्त महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील सं. 309/2021 में उत्तरवादी सं. 2 और रिट अपील सं.438/2022 में उत्तरवादी सं. 4 के लिए	: श्री प्रफुल्ल एन.भारत, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता और श्री मयंक चंद्राकर, अधिवक्ता

आदेश सुरक्षित करने का दिनांक: 07/09/2022

आदेश पारित करने का दिनांक: 30/09/2022

माननीय श्री अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी

सी.ए.वी. निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी के अनुसार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपर्युक्त रिट अपील इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा किया जा रहा है, क्योंकि निर्णय के लिए सामान्य बिंदु शामिल है। निपटान के उद्देश्य से, रिट अपील संख्या 309/2021 में दिए गए तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है।

2. अपीलकर्ता ने रिट अपील संख्या 309/2021 प्रस्तुत की है जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यूपीएस संख्या 3735/2021 में पारित दिनांक 9.8.2021 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके अधीन विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को निरस्त कर दिया है और आक्षेपित आदेश की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी न्यायाधिकरण (इसके बाद 'न्यायाधिकरण') द्वारा दिनांक 5.7.2021 को पारित अनुलग्नक–ए/1) में यह अवलोकन किया गया कि अपीलीय फोरम से अपील में शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि संयुक्त रजिस्ट्रार का आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में दिसंबर, 2009 में ही आदेश पारित कर दिया गया था।

3. आक्षेपित आदेश के अधीन न्यायाधिकरण ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (संक्षेप में 'अधिनियम') में हाल ही में किए गए संशोधन के दृष्टिकोण में अपील को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपीलकर्ता को वापस कर दिया है।

4. प्रकरण के तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी संख्या 2 ने संयुक्त रजिस्ट्रार के दिनांक 27.12.2019 के आदेश को चुनौती देते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। दिनांक 27.12.2019 के उक्त

आदेश के अधीन संयुक्त रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता को बहाल कर दिया। यद्यपि अपील 22.01.2020 को ही प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इसे पंजीकृत नहीं किया जा सका और यह केवल 05.07.2021 को ही पंजीकरण हो पाया। इस बीच,छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1960 दिनांक 14.10.2020 के संशोधन द्वारा संशोधित किया गया और धारा 78 (1) (बी) के अधीन संयुक्त रजिस्ट्रार के आदेश से उत्पन्न अपील का एक नया फोरम प्रदान किया गया। संयुक्त रजिस्ट्रार के आदेश से अपील का अगला फोरम रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत अधिकृत अतिरिक्त रजिस्ट्रार को प्रदान किया गया था। 1960 के पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 78 में लाए गए संशोधित प्रावधान के आधार पर जब उत्तरवादी संख्या 100/2008 की अपील पर विचार किया गया तो रजिस्ट्रार ने कहा कि अपील का अगला फोरम रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत अधिकृत अतिरिक्त रजिस्ट्रार को प्रदान किया गया था। पंजीकरण के लिए 05.07.2021 को आया, न्यायाधिकरण ने निर्णय लिया कि अधिनियम में संशोधन के आलोक में, अब से अपील रजिस्ट्रार या अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष होगी, जैसा भी प्रकरण हो। संशोधन के बाद न्यायाधिकरण के पास अपील का क्षेत्राधिकार नहीं रहा और अपील को उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. रिट कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता का तर्क था कि जिस दिन उत्तरवादी संख्या 2 ने अपील प्रस्तुत की थी, यानी 22.01.2020 को, अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया था और अपील न्यायाधिकरण के समक्ष ही सुनवाई योग्य थी। अपीलकर्ता का यह भी तर्क है कि चूंकि अपील संशोधन से पहले की गई थी, इसलिए संशोधन और संशोधन के माध्यम से प्रदान किए गए उपचार के फोरम को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता था और उस सीमा तक, न्यायाधिकरण अनुलग्नक ए/1 का आदेश गलत है। वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {(2015) 4 एससीसी 33} के प्रकरण का अवलंब लिया गया है जो विधि के एक प्रावधान में संशोधन के आलोक में अधिकार क्षेत्र के पहलू से संबंधित था।

का अवलंब लिया है।

6. इस स्तर पर, यह न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के प्रासंगिक पैरा को पुन: प्रस्तुत करना उचित समझता है।

> " 10. उक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखते हुए, चूंकि पंजीकरण की तिथि या सुनवाई की तिथि यानी 05.07.2021 को ट्रिब्यूनल के पास संयुक्त रजिस्ट्रार के आदेश से उत्पन्न अपील पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। ट्रिब्यूनल ने अपील को संबंधित अपीलीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सही तरीके से वापस कर दिया है।
>
> 11. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय के संबंध में, इसे पूरी तरह से अलग

संविदात्मक पृष्ठभूमि के अधीन पारित किया गया था और जहां विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपीलों का एक सेट पहले ही सुना और स्वीकार किया गया था, केवल इसलिए कि उनमें से एक अपील संशोधन के बाद प्रस्तुत की गई थी और संशोधन प्रावधान के आलोक में अधिकार क्षेत्र के आधार पर इसे निरस्त कर दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि इसे निरस्त नहीं किया जा सकता था, खासकर जब उसी आदेश से उत्पन्न अन्य मामलों पर विचार किया गया हो।

12. संशोधन की प्रयोज्यता या पूर्वव्यापी प्रभाव के संबंध में, इस न्यायालय का मत है कि चूंकि संशोधन के आधार पर, अपील का एक नया फोरम निर्धारित किया गया है, यदि पक्षकारों को उक्त अपील फोरम का लाभ उठाने की अनुमति नहीं है और न्यायाधिकरण अपील पर विचार करना जारी रखता है, भले ही वह संशोधन से पहले पारित आदेशों के संबंध में हो, तो इससे पक्षों में से एक को आगे अपील के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, जो अन्यथा संशोधन के आधार पर बनाए गए विधि के अधीन प्रदान किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के इस तर्क के संबंध में कि न्यायाधिकरण अभी भी उन सभी अपीलों पर कब्जा किए हुए है जो संशोधन के लागू होने से पहले पंजीकृत की गई थीं। इस समय यह न्यायालय केवल इतना ही देख सकता है कि वर्तमान रिट याचिका में यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दिए गए आदेश तक ही सीमित रहेगा। उन सभी मामलों में पक्षकारों का अधिकार अधिकरण के समक्ष इसे उठाने के लिए सुरक्षित है, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं और तदनुसार उचित आदेश या राहत प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे निर्णय जो अभी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा आक्षेपित किए जा सकते हैं। वर्तमान रिट याचिका में सीमित रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय उन मामलों पर टिप्पणी करने और उन पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होगा जो अधिकरण के समक्ष लंबित हैं, विशेष रूप से, जब उन विवादों के पक्षकार वर्तमान याचिका में इस न्यायालय के समक्ष नहीं हैं।

14. उक्त टिप्पणियों को देखते हुए, यह न्यायालय दिनांक 05.07.2021 को आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक ए/1) पारित करने के दौरान अधिकरण की ओर से कोई क्षेत्राधिकार से सम्बंधित त्रुटि या अवैधता नहीं पाता है। रिट याचिका विफल होती है और तदनुसार निरस्त की जाती है।"

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

8. श्री स्वाई, रिट अपील संख्या 309/2021 में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश कि सुनवाई की तिथि यानी 5.7.2021 को न्यायाधिकरण के पास प्रकरण की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, उचित नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि संशोधन हमेशा संभावित होते हैं जब तक कि इसके पूर्वव्यापी आवेदन के बारे में कोई विशेष उल्लेख न हो। श्री अमन सक्सेना, रिट अपील संख्या 438/2022 में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सीआईटी बनाम धाडी साहू[1] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेका अवलंब लिया है। रहे हैं।

9. इसके विपरीत, श्री भरत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तरवादी – जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर की ओर से उपस्थित हुए, ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के पास कार्रवाई का अधिकार हो सकता है, लेकिन फोरम का अधिकार नहीं है। उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा[2], मारिया क्रिस्टीना डी सूजा सोडर बनाम अमरिया जुराना परेरा पिंटो[3], वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (पूर्वोक्त) और अभ्युदय कुमार शाही बनाम भारत प्रधान फिलिंग सेंटर[4] के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी न्यायाधिकरण को अधिनियम (क्रमांक 17, 1961) की धारा 78 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्रमांक 18, 2020) द्वारा दिनांक 14.10.2020 से लागू हुए संशोधन के समक्ष प्रस्तुत लंबित अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार है?

11. वर्तमान प्रकरण में शामिल विवाद्यक पर निर्णय लेने के लिए अधिनियम की धारा 78 के प्रासंगिक प्रावधानों और छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्रमांक 18, 2020) द्वारा शामिल नव संशोधित धारा 78 को पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो प्रासंगिक हैं और निम्नानुसार पढ़े जाएंगे:

> "78. रजिस्ट्रार और न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलें.–
>
> (1) सिवाय इसके कि जहां अन्यथा प्रावधान किया गया है, इस अधिनियम या इसके

1 1994 Supp (1) SCC 257
2 (1975) 2 SCC 840
3 (1979) 1 SCC 92
4 (2022) 6 SCC 522

अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश के विरुद्ध अपील होगी:–

(क) यदि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, जो अतिरिक्त रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार के अलावा अन्य हो, चाहे आदेश पारित करने वाले अधिकारी को रजिस्ट्रार की शक्तियां प्राप्त हों या नहीं, तो रजिस्ट्रार को;

(ख) यदि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया जाता है, तो न्यायाधिकरण को।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा प्रथम अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध न्यायाधिकरण में केवल निम्नलिखित आधारों पर द्वितीय अपील की जा सकेगी, अर्थात्:–

XXXX

(3) मूल अधिनियम की धारा 78 का संशोधन (14.10.2020 से प्रभावी) मूल अधिनियम की धारा 78 में, –

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1) सिवाय जहां अन्यथा उपबंधित किया गया है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी:—

(क) यदि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, जो अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार के अलावा अन्य हो, चाहे आदेश पारित करने वाले अधिकारी को रजिस्ट्रार की शक्तियां प्राप्त हों या नहीं, संयुक्त रजिस्ट्रार को;

(ख) यदि ऐसा आदेश संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया जाता है, तो रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से विधिवत् प्राधिकृत रजिस्ट्रार या अतिरिक्त रजिस्ट्रार को।

(ग) यदि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार या अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया जाता है, तो न्यायाधिकरण को।

(ii) उपधारा

(2) में "रजिस्ट्रार द्वारा प्रथम अपील" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्रथम अपील" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"

12. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6, जो निरसन के प्रभाव से संबंधित है, इस प्रकार है:

6. निरसन का प्रभाव– जहां कि यह अधिनियम या इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाया गया कोई [केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम अब तक बनाई गई या एतत्पश्चात् बनाई जाने वाली किसी अधिनियमिति को निरसित कर देता है वहां जब तक कि भिन्न

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आशय प्रतीत न हो वह निरसन–

(क) उस निरसन के प्रभावशील होने के समय अप्रवृत्त या अविद्यमान किसी बात को, पुनरुज्जीवित नहीं करेगा ; अथवा

(ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा ; अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा ; अथवा

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा ; अथवा

(ड) किसी यथा पूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में के किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा, और ऐसा कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई भी शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो वह निरसन करने वाला अधिनियम पारित ही न हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सामान्यतः, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 लागू होती है और कार्यवाही को जारी रखने में सक्षम बनाती है जैसे कि अधिनियम को रोका नहीं गया था जब तक कि निरसन अधिनियम में अलग इरादा प्रकट न हो। यदि विशिष्ट प्रावधान और इरादा स्पष्ट रूप से उक्त अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान के साथ असंगत हैं और वे स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, तो नया अधिनियम लागू होगा। इस विवाद्यक पर विचार करने से पहले, विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देना उचित होगा, जहाँ अपील के फोरम में परिवर्तन में संशोधन के प्रभाव और लंबित मामलों पर इसके परिणामों से निपटा गया है।

14. महाराष्ट्र राज्य बनाम विजय वामन पाटिल और अन्य[5] में, यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है:–

> "19. इस पहलू की उचित विवेचना के लिए, वैधानिक व्याख्या के कुछ प्रासंगिक सिद्धांतों का संदर्भ लेना आवश्यक होगा, जो समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित हैं।
>
> 20. माननीय न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा लिखित "वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत" (11 वां संस्करण) 2008 में निम्नलिखित सिद्धांत बताये गए हैं: – "फोरम में परिवर्तन लाने वाला कोई नया विधि लंबित

5 2009 SCC OnLine Bom 944

कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं करता, जब तक कि इसमें कार्यवाही में परिवर्तन के लिए कोई प्रावधान न किया गया हो या कोई अन्य स्पष्ट संकेत न हो कि लंबित कार्रवाइयां प्रभावित हुई हैं। इस प्रकार, यदि सिविल न्यायालय में किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान बनाए गए नए विधि में यह लिखा हो कि "किसी भी सिविल न्यायालय को राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुछ प्रश्नों को निपटाने, निर्णय लेने या उनसे निपटने का अधिकार नहीं होगा" और लंबित मुकदमा इन प्रश्नों से संबंधित है, तो सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा।" "यह सिद्धांत कि लंबित कार्यवाही प्रभावित नहीं होती, इससे आगे नहीं जाता कि प्रत्येक प्रकरण में विधि की भाषा की जांच की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या विधानमंडल का स्पष्ट रूप से लंबित कार्यवाही को भी विधि के दायरे में लाने का इरादा है।" (पृष्ठ 542 अध्याय VI)"

15. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा[6] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5. धारा 110–ए और 110–एफ की स्पष्ट भाषा पर यह विचार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि विधि में परिवर्तन केवल फोरम का परिवर्तन था, अर्थात विशेषण या प्रक्रियात्मक विधि का परिवर्तन, न कि मूल विधि का। यह एक सुस्थापित प्रस्ताव है कि विधि का ऐसा परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है और व्यक्ति को नए फोरम में जाना होगा, भले ही उसका कार्रवाई का कारण या कार्रवाई का अधिकार फोरम के परिवर्तन से पहले ही प्राप्त हो गया हो। उसके पास कार्रवाई का निहित अधिकार होगा, लेकिन फोरम का निहित अधिकार नहीं होगा। यदि स्पष्ट शब्दों में नया फोरम केवल फोरम के निर्माण के बाद उत्पन्न होने वाले कार्रवाई के कारणों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो विधि का पूर्वव्यापी संचालन समाप्त हो जाता है। अन्यथा सामान्य नियम इसे पूर्वव्यापी बनाना है। उप–धारा (1) में होने वाली "दुर्घटना से उत्पन्न" और उप–धारा (2) में उल्लिखित "जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई" अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि फोरम का परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होना था, चाहे दुर्घटना कब हुई हो। उस सीमा तक उत्तर को सरल तरीके से देने में कोई कठिनाई नहीं थी।

16. मारिया क्रिस्टीना डी सूजा सोडर (पूर्वोक्त) में पैरा–5 में निम्न प्रकार से कहा गया है :–

6 (1975) 2 SCC 840

" 5. ..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपील का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह विवाद शुरू होते ही वादी को प्राप्त हो जाता है, तथा ऐसा अधिकार या उससे संबंधित कोई उपाय ऐसे अधिकार प्रदान करने वाले अधिनियम के किसी निरसन से प्रभावित नहीं होगा, जब तक कि निरसन अधिनियम स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा उससे संबंधित ऐसे अधिकार या उपाय को समाप्त न कर दे। यह स्थिति केन्द्रीय अधिनियम 30, 1965 की धारा 4 के परन्तुक के खण्ड (बी) और (सी) द्वारा स्पष्ट की गई है, जो सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के खण्ड (सी) और (ई) के अनुरूप है। यह स्थिति प्रिवी काउंसिल और इस न्यायालय के निर्णयों (देखें कोलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम इरविंग [1905 एसी 369] और गरिकापट्टी वीरैया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी [1957 एससीआर 488]) द्वारा भी तय की गई है, लेकिन वह फोरम जहां ऐसी अपील प्रस्तुत की जा सकती है, निस्संदेह एक प्रक्रियात्मक प्रकरण है और इसलिए अपील, जिसका अधिकार एक निरस्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न हुआ है, उसे निरस्त अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए फोरम में प्रस्तुत करना होगा। अपील का फोरम और इसके लिए सीमाएं भी संबंधित प्रकरण हैं। प्रक्रियात्मक विधि के बारे में यह बात सैल्मंड के न्यायशास्त्र (12 वें संस्करण) के पृष्ठ 462 पर दिए गए निम्नलिखित अंश से स्पष्ट हो जाएगी: "क्या मुझे कुछ संपत्ति वापस पाने का अधिकार है, यह एक मौलिक विधि का प्रश्न है, क्योंकि ऐसे अधिकारों का निर्धारण और संरक्षण न्याय प्रशासन के उद्देश्यों में से एक है; लेकिन मुझे किन न्यायालयों में और कितने समय के भीतर कार्यवाही शुरू करनी चाहिए, यह प्रक्रियात्मक विधि का प्रश्न है, क्योंकि वे केवल उन तरीकों से संबंधित हैं, जिनसे न्यायालय अपने कार्य पूरा करते हैं।" यह सच है कि 1965 के केंद्रीय अधिनियम 30 की धारा 4 के प्रावधान के खंड (सी) में, जो सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 (ई) के अनुरूप है, यह प्रावधान किया गया है कि अपील के अधिकार जैसे निहित अधिकार के संबंध में एक उपाय या विधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जारी रखी जा सकती है या लागू की जा सकती है जैसे कि यह अधिनियम (अर्थात निरसन अधिनियम) पारित नहीं हुआ था। लेकिन यह प्रावधान केवल ऐसे निहित अधिकार के संबंध में उपाय या विधिक कार्यवाही को बचाता है जो वादी के लिए निरसन के बावजूद अपनाने के लिए खुला है, लेकिन इस प्रावधान का उस फोरम से कोई लेना–देना नहीं है जहां उपाय या विधिक कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाना है। यदि निरसन अधिनियम नया फोरम प्रदान करता है जहां ऐसे निहित अधिकार के संबंध में उपाय या विधिक कार्यवाही को निरसन के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है, तो फोरम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को निरसन अधिनियम में दिए गए अनुसार होना चाहिए। हम बता सकते हैं कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 (ई) के बारे में ऐसा दृष्टिकोण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुरुषोत्तम सिंह बनाम नारायण सिंह और राजस्थान राज्य [एआईआर 1955 राज 203] के प्रकरण में लिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निरसन अधिनियम (अधिनियम 30, 1965) के अधीन गोवा अधिनियम (अधिनियम 16, 1965) के साथ अपील न्यायिक आयुक्त की न्यायालय में की जानी थी और उसे तदनुसार उचित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

17. वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (पूर्वोक्त) में पैरा 44 से 46 में निम्नानुसार देखा गया है:

"44. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि छुटकारे के प्रावधान के अभाव में लंबित कार्यवाही (और उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र) छुटकारे के योग्य नहीं मानी जा सकती। हमारे लिए इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है। अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अमृत लाल एंड कंपनी [(2001) 8 एससीसी 397] में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में यह माना गया था कि सामान्य सिद्धांत यह है कि कोई ऐसा विधि जो फोरम में बदलाव लाता है, लंबित कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं करेगा, जब तक कि इसके विपरीत इरादा स्पष्ट रूप से न दिखाया गया हो। चूंकि इसमें संशोधन ऐसा प्रावधान नहीं करता है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि लंबित अपीलें (धारा 15–जेड के संशोधन से पहले) किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगी। तदनुसार, उपरोक्त निर्णय में व्यक्त किए गए समान कारणों से (जिसके प्रासंगिक अंश ऊपर पुन: प्रस्तुत किए गए हैं), हमारा यह विचार है कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तात्कालिक तर्क पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6(सी) और (ई) में निहित आदेश के दृष्टिकोण में तात्कालिक तर्क पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय ने माना है कि किसी विधि का संशोधन, जो पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होता है, लंबित कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है, सिवाय इसके कि संशोधन प्रावधान स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से अन्यथा प्रदान करता है। लंबित कार्यवाही इस प्रकार जारी रहनी चाहिए जैसे कि असंशोधित प्रावधान अभी भी लागू है। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला है कि जब कोई विवाद शुरू होती है, तो उस तिथि पर पक्षों के सभी अधिकार और दायित्व स्पष्ट हो जाते हैं, और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 का अधिदेश केवल यह सुनिश्चित करता है कि असंशोधित प्रावधान के अधीन लंबित कार्यवाही अप्रभावित रहे। इसलिए, यहां भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हमारा निष्कर्ष वही है जो हमने पहले ही पूर्वगामी पैरा में दिया है।

45. पूर्वगामी पैरा में व्यक्त तरीके से निष्कर्ष निकालने के बाद, हमारे लिए अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क की जांच करना आवश्यक नहीं है, अर्थात, सेबी अधिनियम की धारा 15–जेड में संशोधन, दूसरे अपीलीय उपाय के फोरम में केवल बदलाव की कल्पना करता है। उपर्युक्त के बावजूद, हम वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, उपरोक्त विषय पर भी गहनता से विचार करना उचित और उपयुक्त मानते हैं। फोरम के विषय पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन पर विचार करते हुए, हम काल्पनिक रूप से यह मान लेंगे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा धारा 15–जेड में किए गए संशोधन का पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए द्वितीय अपीलीय उपाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तथा इसके अतिरिक्त, उपरोक्त संशोधन केवल द्वितीय अपील के फोरम को उच्च न्यायालय (असंशोधित प्रावधान के अधीन) से बदलकर सर्वोच्च न्यायालय (संशोधन के परिणामस्वरूप) कर देता है। उपरोक्त धारणा के आधार पर, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा मारिया क्रिस्टीना डी सूजा सोडर [मारिया क्रिस्टीना डी सूजा सोडर बनाम अमरिया जुराना परेरा पिंटो, (1979) 1 एससीसी 92], हितेंद्र विष्णु ठाकुर [हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1994) 4 एससीसी 602: 1994 एससीसी (क्रि) 1087] और थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड [थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2011) 6 एससीसी 739: (2011) 3 एससीसी (सिविल) 458] मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि फोरम से संबंधित विधि प्रकृति में प्रक्रियात्मक है, एक संशोधन जो फोरम को बदल देता है, पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। जबकि उपर्युक्त तर्क की सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह एक पूर्ण नियम नहीं है। इस संबंध में, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से धाड़ी साहू प्रकरण में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है [सीआईटी बनाम धाड़ी साहू, 1994 सप (1) एससीसी 257] जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि फोरम में संशोधन आवश्यक रूप से प्रक्रिया का मुद्दा नहीं होगा। उपरोक्त निर्णय में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहां प्रश्न फोरम में परिवर्तन का है, यह प्रक्रिया का प्रश्न नहीं रह जाता है, और यदि कार्यवाही पहले निर्धारित फोरम (संशोधन के प्रभावी होने से पहले) के समक्ष शुरू हो जाती है, तो यह मूल और निहित हो जाता है। इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से घोषित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया है कि यदि संशोधन से पहले अपीलीय उपाय का लाभ उठाया गया था (असंशोधित प्रावधान में व्यक्त फोरम के समक्ष), तो यह एक निहित अधिकार होगा। यद्यपि, यदि इसका लाभ नहीं उठाया गया है, और अपीलीय उपाय के फोरम को संशोधन द्वारा बदल दिया गया है, तो फोरम में परिवर्तन एक प्रक्रियात्मक संशोधन होगा, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है। परिणामस्वरूप, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में भी, बोर्ड द्वारा 29–10–2002 से पहले प्रस्तुत की गई सभी अपीलों को निहित के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, और तदनुसार उनका न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए।

46. उपरोक्त पैरा में हमारे द्वारा दर्ज निष्कर्ष सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 में निहित आदेश से भी उभर कर आता है। उपर्युक्त धारा 6 से उभरने वाली विधिक रूपरेखा हमारे द्वारा पहले ही दर्ज कर ली गई है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. सेबी बनाम क्वासिक क्रेडिट लिमिटेड[7] में, यह इस प्रकार माना गया है:–

"54. उपरोक्त निर्णयों में निकाले गए निष्कर्षों के अवलोकन से, हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि "फोरम" का परिवर्तन मूल या प्रक्रियात्मक हो सकता है। यह प्रक्रियात्मक हो सकता है जब उपाय का लाभ अभी तक नहीं उठाया गया हो, लेकिन जहां उपाय का लाभ पहले ही उठाया जा चुका है (मौजूदा वैधानिक प्रावधान के अधीन) अधिकार को एक निहित मूल अधिकार के रूप में क्रिस्टलीकृत माना जा सकता है।"

19. अभ्युदय कुमार शाही बनाम भारत प्रधान फिलिंग सेंटर[8] में, अपील के लंबित रहने के दौरान, दिशानिर्देशों में संशोधनों के दृष्टिकोण में अपीलीय फोरम बदल गया था; और विवाद समाधान फोरम, जैसा कि पहले प्रदान किया गया था, अस्तित्व में नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि संशोधित दिशा–निर्देशों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, जो यह प्रावधान करते हैं कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड के निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होंगे। इसलिए, इस तरह की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, पैरा 9 में, यह निम्नानुसार माना गया:

"9. उपर्युक्त बाद की घटनाओं के दृष्टिकोण में, यह स्पष्ट है कि वर्तमान उत्तरवादी ने

7 (2018) 13 SCC 1
8 (2022) 6 SCC 522

पूर्ववर्ती तंत्र के माध्यम से अपील के निर्णय के लिए अपना आग्रह छोड़ दिया है, और यह सही भी है क्योंकि, भले ही उत्तरवादी (रिट याचिकाकर्ता) के पास अपील पर विचार करने का अधिकार था, लेकिन उसके पास उस फोरम द्वारा अपील पर विचार करने के लिए आग्रह करने का कोई समान अधिकार नहीं था जो अब अस्तित्व में नहीं था।"

20. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नीना अनेजा बनाम जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड[9] के प्रकरण में, विभिन्न निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है:

"72. लंबित कार्यवाही और पूर्वव्यापीता पर फोरम में बदलाव के प्रभाव की व्याख्या करने वाले असंख्य उदाहरणों पर विचार करते हुए – विधि की एक स्पष्ट स्थिति सामने आई है: फोरम में बदलाव प्रक्रिया के दायरे में आता है। तदनुसार, प्रक्रियात्मक विधि पर लागू वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों के अनुपालन में, प्रक्रिया के मामलों में संशोधन पूर्वव्यापी हैं, जब तक कि विधि से कोई विपरीत इरादा सामने न आए। यह स्थिति न्यू इंडिया एश्योरेंस [न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा, (1975) 2 एससीसी 840], मारिया क्रिस्टीना [मारिया क्रिस्टीना डी सूजा सोडर बनाम अमरिया जुराना परेरा पिंटो, (1979) 1 एससीसी 92], हितेंद्र विष्णु ठाकुर [हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1994) 4 एससीसी 602: 1994 एससीसी (क्रि) 1087], रमेश कुमार सोनी [रमेश कुमार सोनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2013) 14 एससीसी 696: (2014) 4 एससीसी (क्रि) 340] और सुधीर जी अंगुर [सुधीर जी अंगुर बनाम एम संजीव, (2006) 1 एससीसी 141]। हाल ही में, मनीष कुमार बनाम भारत संघ [मनीष कुमार बनाम भारत संघ, (2021) 5 एससीसी 1: (2021) 3 एससीसी (सिविल) 50] में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में इस स्थिति को नोट किया गया है। यद्यपि, धादी साहू [सीआईटी बनाम धादी साहू, 1994 सप (1) एससीसी 257] में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में विचलन हुआ, जिसने न्यू इंडिया एश्योरेंस [न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा, (1975) 2 एससीसी 840] में एक बड़ी तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले और मारिया क्रिस्टीना [मारिया क्रिस्टीना डी सूजा सोडर बनाम अमरिया जुराना परेरा पिंटो, (1979) 1 एससीसी 92] में एक समन्वित दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को नजरअंदाज कर दिया। ढाढ़ी साहू में निर्णय [सीआईटी बनाम धाड़ी साहू, 1994 सप्लिमेंट (1) एससीसी 257] ने एक पद प्रतिपादित किया वह: (धाडी साहू प्रकरण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9 (2022) 2 SCC 161

[सीआईटी बनाम ढाडी साहू, 1994 सप्लिमेंट (1) एससीसी 257], एससीसी पी. 262, पैरा 21)

"21. ... प्रक्रियात्मक विधि के प्रकरण में किसी भी वादी के पास कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन जहां फोरम के परिवर्तन का सवाल है, वह केवल प्रक्रिया का सवाल नहीं रह जाता है। अपील या कार्यवाही का फोरम एक निहित अधिकार है, जो किसी विशेष फोरम के समक्ष अपनाई जाने वाली शुद्ध प्रक्रिया के विपरीत है। यह अधिकार तब निहित हो जाता है जब न्यायाधिकरण में कार्यवाही शुरू की जाती है।" (बल दिया गया) इस दृष्टिकोण को लेते हुए, दो न्यायाधीशों की पीठ ने बाध्यकारी निर्णयों पर विचार नहीं किया। धाड़ी साहू [सीआईटी बनाम धाड़ी साहू, 1994 सप (1) एससीसी 257] यह विचार करने में विफल रहा कि मोहम्मद इदरीस [मोहम्मद इदरीस बनाम सत नारायण, (1966) 3 एससीआर 15: एआईआर 1966 एससी 1499] और मनुजेंद्र दत्त [मनुजेंद्र दत्त बनाम पूर्णेदु प्रोसाद रॉय चौधरी, (1967) 1 एससीआर 475: एआईआर 1967 एससी 1419] में दिए गए फैसले में उन वादियों के निहित अधिकारों की रक्षा की गई थी, जो निरस्त करने वाले अधिनियमों से प्रभावित हो रहे थे, न कि इसलिए कि कार्यवाही शुरू होने के बाद फोरम का अधिकार अर्जित होता है। इसके बाद, धाड़ी साहू [सीआईटी बनाम धाड़ी साहू, 1994 सप (1) एससीसी 257] के निर्णयों की एक श्रृंखला आई, जिसमें कहा गया कि कार्यवाही शुरू होने के बाद वादी को फोरम का क्रिस्टलीकृत अधिकार प्राप्त होता है। संशोधन या निरसन से पहले वादी के निहित अधिकार (अपील का अधिकार सहित) निस्संदेह सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के अधीन परिकल्पित मूल अधिकारों के अतिरिक्त सुरक्षित हैं। यह संरक्षण प्रक्रिया के शुद्ध मामलों तक विस्तारित नहीं है। फोरम में परिवर्तन करने वाले निरसन या संशोधन आम तौर पर लंबित कार्यवाही को प्रभावित करेंगे, जब तक कि निरसन या संशोधन विधि से विपरीत इरादा प्रकट न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. ईसीजीसी लिमिटेड बनाम मोकुल श्रीराम ईपीसी जेवी[10] में, निम्नलिखित देखा गया:

"29. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नीना अनेजा [नीना अनेजा बनाम जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, (2022) 2 एससीसी 161: (2022) 1 एससीसी (सिविल) 768] में, इस न्यायालय ने माना कि फोरम का अधिकार एक अर्जित अधिकार नहीं है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6(ई) उपार्जित अधिकार के प्रवर्तन के लिए

10 (2022) 6 SCC 704

लंबित विधिक कार्यवाही को निरसन के प्रभाव से बचाती है; इसका मतलब यह नहीं है कि किसी विशेष फोरम पर विधिक कार्यवाही निरसन के प्रभाव से बचाई गई थी। इस न्यायालय ने पाया कि निरसन अधिनियम में कोई स्पष्ट इरादा नहीं था कि सभी लंबित प्रकरण 2019 अधिनियम के अधीन बनाए गए मंचों में स्थानांतरित हो जाएंगे।

22. उपरोक्त विधिक कथन से, निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं:–

(i) केवल फोरम का परिवर्तन प्रक्रियात्मक विधि का परिवर्तन है और विधि का ऐसा परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है और व्यक्ति को नए फोरम पर जाना पड़ता है, भले ही उसका कार्रवाई का कारण या कार्रवाई का अधिकार फोरम के परिवर्तन से पहले उपार्जित हो।

(ii) फोरम में परिवर्तन लंबित मामलों को प्रभावित नहीं करता है, जब तक कि निरसन अधिनियम स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा स्पष्ट रूप से लंबित कार्यवाही को भी विधि के दायरे में लाने का इरादा नहीं रखता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के पुनर्गठन के बाद, छत्तीसगढ़ सहकारी (संशोधन) अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था और लंबित मामलों के हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित प्रावधान डाला गया था:–

> **"80 ई. लंबित मामलों का हस्तांतरण** – मूल अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने की तारीख को राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जाएगी।**"**

24. इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 6, वर्ष 2013) में अध्याय–X के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान जोड़ा गया तथा उक्त अध्याय में लंबित मामलों के हस्तांतरण के संबंध में धारा 80–डी जोड़ी गई, जो इस प्रकार है:–

> "80–डी. लंबित मामलों का हस्तांतरण – इस अधिनियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी न्यायाधिकरण के गठन की तिथि से ठीक पहले राज्य सरकार के समक्ष लंबित प्रत्येक अपील या कोई अन्य कार्यवाही, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से न्यायाधिकरण को हस्तांतरित मानी जाएगी।"

25. उपरोक्त विधिक घोषणाओं के दृष्टिकोण में, यदि हम वर्तमान मामलों के तथ्यों की जांच करें, तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2020 में सहकारी न्यायाधिकरण से लंबित अपील को उक्त अधिनियम द्वारा स्थापित नए फोरम में स्थानांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जो ऐसे न्यायाधिकरण के समक्ष पहले से प्रस्तुत लंबित अपील मामलों की सुनवाई के लिए है। इसलिए, लंबित अपीलें जो दिनांक 14.10.2020 के संशोधन से पहले प्रस्तुत की गई थीं, उन्हें असंशोधित अधिनियम में उपलब्ध फोरम में जारी रखा जाएगा, और ऐसे संशोधन के बाद प्रस्तुत की जाने वाली अपीलें नए विधि द्वारा शासित होंगी।

26. अपीलकर्ता अमित कुमार जायसवाल ने संशोधन से पहले अधिनियम की धारा 78 के अधीन न्यायाधिकरण के समक्ष निर्विवाद रूप से अपनी अपील प्रस्तुत की है। इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारणों में से एक यह है कि प्रकरण किसी न किसी कारण से पंजीकृत नहीं किया गया था और मूल अधिनियम में धारा 78 (1) (बी) में संशोधन किया गया था, जो स्वीकार्य नहीं है। इस उद्देश्य के लिए दाखिल करने की तारीख महत्वपूर्ण है, न कि पंजीकरण की तारीख, क्योंकि दाखिल करने की तारीख पर न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र है और संशोधन अस्तित्व में नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. रिट अपील संख्या 438/2022 में अपीलकर्ता अंशुमान पांडे ने संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के 27.12.2019 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जो विषय संशोधन से पहले माना जाता है, और ट्रिब्यूनल ने संशोधन के दृष्टिकोण में नए फोरम के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली लंबित अपील को वापस कर दिया, और तदनुसार अपीलकर्ता अंशुमान पांडे ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के समक्ष एक नई अपील प्रस्तुत की है, जिन्होंने इस बात पर विचार करने के बाद कि इसी तरह के प्रकरण में यानी अमित कुमार जायसवाल (रिट अपील 309/2021) के प्रकरण में, इस न्यायालय ने दिनांक 16–11–2021 के आदेश के अधीन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 9.8.2021 को डब्ल्यूपी (एस) संख्या 3735/2021 में पारित आदेश को निलंबित कर दिया है और उत्तरवादी संख्या 2 के कहने पर रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाही को निलंबित कर दिया है। अपीलकर्ता अंशुमान पांडे द्वारा प्रस्तुत अपील के दिनांक 6.5.2022 के आदेश के अनुसार रिट अपील संख्या 309/2021 के परिणाम तक। उक्त आदेश को रिट याचिका (सेवा) संख्या 4710/2022 में चुनौती दी गई थी जिसमें रिट कोर्ट ने रिट अपील 309/2021 के निपटारे के बाद प्रकरण को सूचीबद्ध करने के लिए 08.07.2022 को एक आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने यह अपील प्रस्तुत की है।

28. हम अपीलकर्ता अंशुमान पांडे के प्रकरण में रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 6.5.2022 को पारित आदेश और रिट याचिका (सेवा) संख्या 4710/2022 में रिट कोर्ट द्वारा दिनांक 8.7.2022 को पारित आदेश में कोई कमी नहीं पाते हैं।

29. उपर्युक्त कारणों से, ट्रिब्यूनल द्वारा पारित दिनांक 05/07/2021 का आदेश जिसके अधीन अपील को नए फोरम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया गया था और जिसे WP (S) संख्या 3735/2021 में दिनांक 09/08/2021 के आदेश द्वारा यथावत रखा गया था, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

30. परिणामस्वरूप, रिट अपील संख्या 309/2021 को स्वीकार की जाती है और रिट अपील संख्या 438/2022 को निरस्त किया जाता है।

31. रजिस्ट्री 12.10.2022 को रोस्टर वाली उपयुक्त एकल पीठ के समक्ष रिट याचिका (सेवा) संख्या 3735/2021 को सूचीबद्ध करेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/– (अरूप कुमार गोस्वामी) मुख्य न्यायाधिपति	सही/– (दीपक कुमार तिवारी) न्यायमूर्ति

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।